V सहकारी बैंकिंग घटनाक्रम

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की जमा वृद्धि में वर्ष 2023-24 में सुधार हुआ और ऋण वृद्धि सतत बनी रही। यूसीबी के वित्तीय प्रदर्शन में उच्च लाभप्रदता, मजबूत पूंजी बफर और कम सकल सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के अनुपात के कारण सुधार हुआ। राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों के सापेक्ष अधिक रहा।

1. परिचय

V.1 सहकारी बैंक भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास का समर्थन करने में। वर्षों से, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए गए हैं जैसे– इस क्षेत्र के दोहरे विनियमन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक की विनियामक शक्तियों का विस्तार; पूंजी जुटाने के लिए सहकारी बैंकों को अधिक स्वतंत्रता; और इस क्षेत्र में जमाकर्ताओं के विश्वास बढ़ाने के लिए जमा बीमा सुधार। रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2024 में टियर 2 से 4 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिये एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क की शुरुआत की और टियर 1 यूसीबी के लिये निगरानी बढ़ाई, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

V.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय समीक्षाधीन अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रदर्शन पर केंद्रित है।[1] खंड 2 में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की विकसनशील संरचना पर चर्चा की गई है, इसके बाद खंड 3 में यूसीबी की लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया है। खंड 4 अल्पकालिक और दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों के वित्तीय प्रदर्शन की जांच करता है। इसके बाद खंड 5 में एक समग्र मूल्यांकन किया गया है।

2. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना

V.3 सहकारी बैंकिंग संरचना, जिसमें यूसीबी और ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां (आरसीसी) शामिल हैं, सीमांत उधारकर्ताओं को उधार देने और गांवों और छोटे शहरों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर ज़ोर देकर वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों की सहायता करती है। यूसीबी को अनुसूचित या गैर-अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इस आधार पर कि क्या वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं[2] और उनकी भौगोलिक पहुँच (एकल-राज्य या बहु-राज्य) है। आरसीसी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक संस्थानों में वर्गीकृत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 1,472 यूसीबी और 1,07,961 आरसीसी थे[3] (चार्ट V.1)। संस्थाओं की संख्या के संदर्भ में, 97 प्रतिशत से अधिक कुल सहकारी क्षेत्र, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

[1] यद्यपि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) और दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां रिज़र्व बैंक के विनियामक कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, विश्लेषण की पूर्णता के लिए उनके क्रियाकलापों और प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में दिया गया है।

[2] अनुसूचित सहकारी बैंकों के अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भी अधिनियम की इसी अनुसूची में शामिल किया गया है।

[3] पीएसीएस, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) के डेटा एक वर्ष के अंतराल के साथ उपलब्ध हैं, अर्थात, वे वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं।

चार्ट V.1: ऋण सहकारी समितियों की संरचना

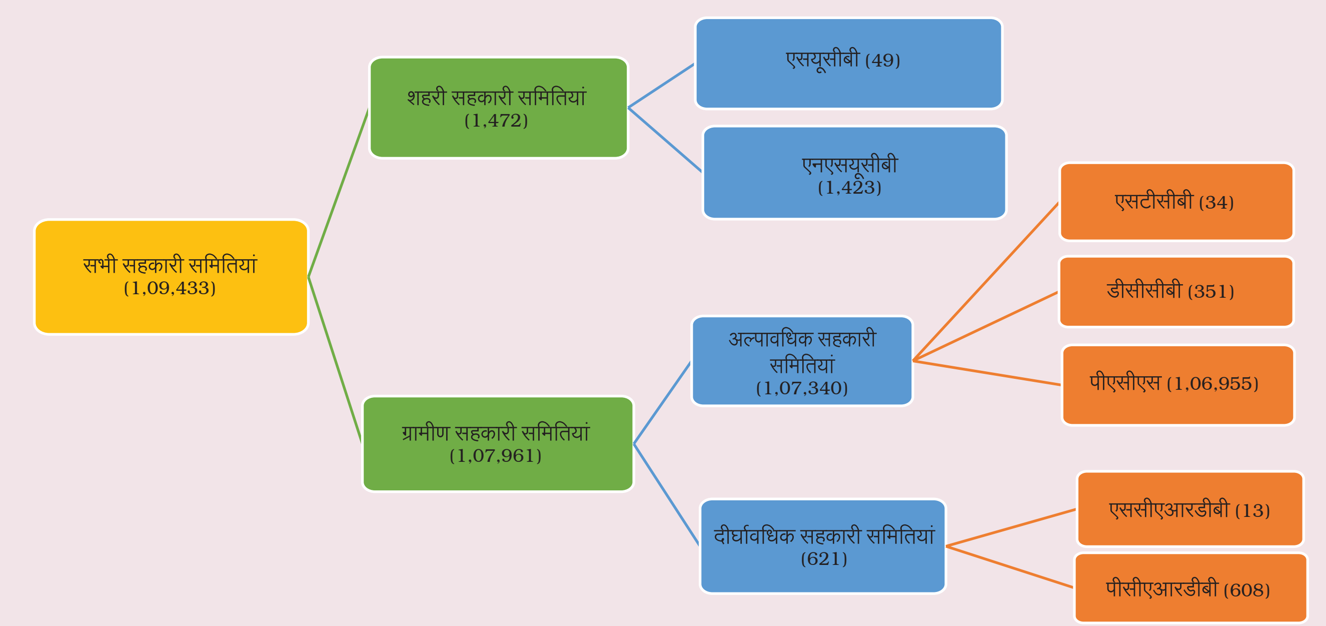

टिप्पणियाँ: 1. एसयूसीबी : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक; एनएसयूसीबी: गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक; एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2024 के अंत में यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को और मार्च 2023 के अंत में आरसीसी की संख्या को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का राष्ट्रीय परिसंघ (एनएएफएससीओबी)।

(पीएसीएस) हैं, हालांकि आस्तियों के संदर्भ में, कुल सहकारी खंड में उनका हिस्सा केवल 17.8 प्रतिशत और आरसीसी में 25.3 प्रतिशत है।

V.4 यूसीबी का रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित हैं। बीआर अधिनियम की धारा 35 (6) के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उनका पर्यवेक्षण किया जाता है।

V.5 मार्च 2023 के अंत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की समेकित आस्तियां ₹22.9 लाख करोड़ थीं, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्तियों का लगभग 9.5 प्रतिशत थीं, जो मार्च 2014 के अंत के 11.2 प्रतिशत से कम थीं। सहकारी समिति क्षेत्र की कुल आस्तियों (ग्रामीण और शहरी सहकारी समितियों को मिलाकर) में आरसीसी की हिस्सेदारी 70.4 प्रतिशत है (चार्ट V.2)

चार्ट V.2: आस्ति के आकार के अनुसार ऋण सहकारी समितियों का विभाजन (मार्च 2023 के अंत में)

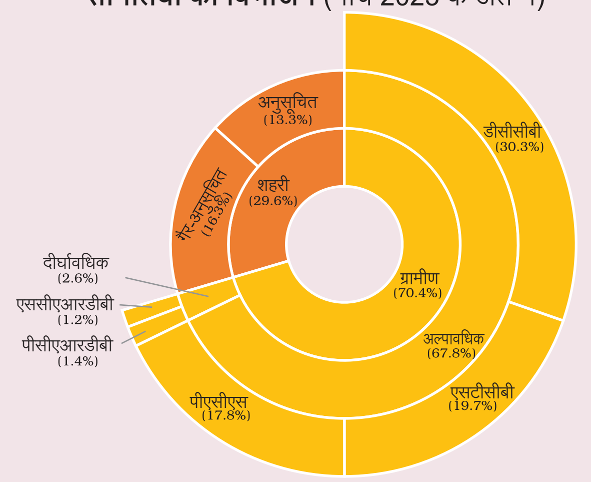

टिप्पणी: सनबर्स्ट चार्ट सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में स्तर को दर्शाता है। चार्ट के प्रत्येक खंड का आकार कुल आस्तियों में उस क्षेत्र की हिस्सेदारी (कोष्ठकों में उल्लिखित) के अनुपात में है।

स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

सारणी V.1 कृषि की ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

	ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक
1	2	3	4
2016-17	13.4	11.6	75.0
2017-18	12.9	12.1	74.9
2018-19	12.1	11.9	76.0
2019-20	11.3	11.9	76.8
2020-21	12.1	12.1	75.8
2021-22	13.0	11.0	76.0
2022-23	11.0	11.2	77.8
2023-24	9.5	11.1	79.4

स्रोत: नाबार्ड (एन्श्योर पोर्टल)।

V.6 ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना कृषि को ऋण देने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। प्रौद्योगिकी और शाखा विस्तार के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती पहुंच के कारण वर्ष 2023-24 में कृषि के कुल ऋण में उनकी हिस्सेदारी लगातार दूसरे वर्ष घटकर 10 प्रतिशत से कम हो गई (सारणी V.1)।

3. शहरी सहकारी बैंक

V.7 उदार लाइसेंसिंग नीति के कारण 1990 के दशक में यूसीबी की संख्या में वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों में, नए लाइसेंस प्राप्त बैंकों में से लगभग एक तिहाई वित्तीय रूप से अस्थिर हो गए। वर्ष 2004-05 से, रिज़र्व बैंक ने एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें गैर-अर्थक्षम यूसीबी को उनके अर्थक्षम समकक्षों के साथ मिलाना, गैर-अर्थक्षम संस्थाओं को बंद करना और नए लाइसेंस

चार्ट V.3: यूसीबी की संख्या

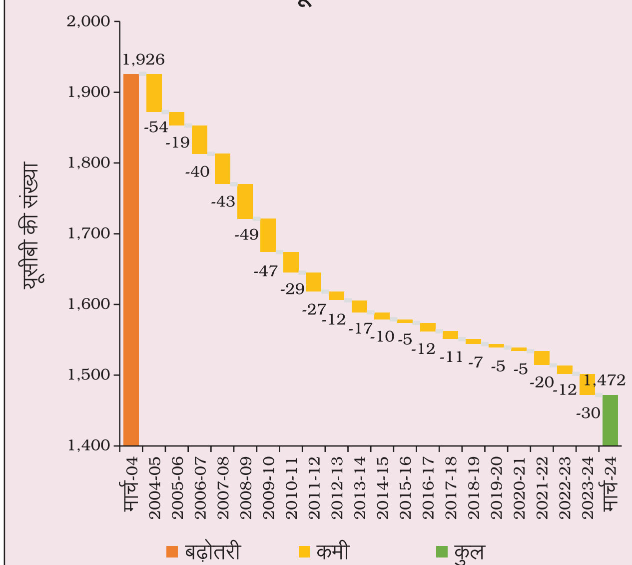

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

जारी करने को निलंबित करना शामिल था। परिणामस्वरूप, पिछले दो दशकों में यूसीबी की संख्या 1,926 से घटकर 1,472 हो गई (चार्ट V.3)।

V.8 वर्ष 2004-05 के बाद से, इस क्षेत्र ने 156 विलय देखे हैं, जिनमें वर्ष 2023-24 में छह शामिल हैं, जिनमें से तीन महाराष्ट्र में थे, दो तेलंगाना में थे और एक गुजरात में था। पिछले दो दशकों में अधिकांश विलय महाराष्ट्र में हुए, इसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा (चार्ट V.4ए)। वर्ष 2023-24

चार्ट V.4: यूसीबी में विलयन अभियान

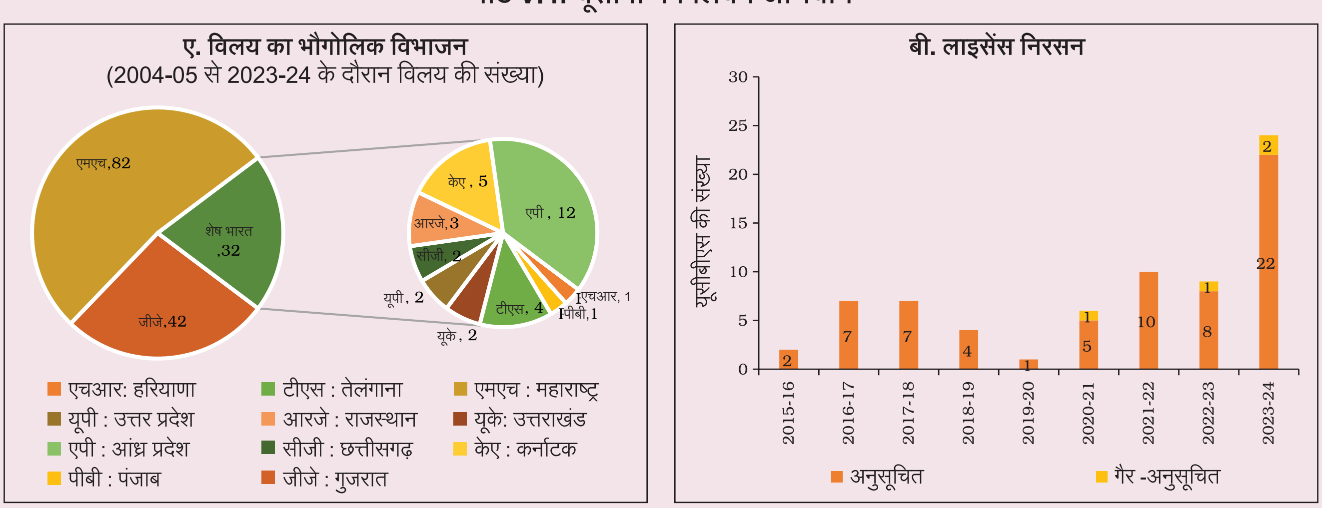

स्रोत: आरबीआई।

के दौरान, 24 यूसीबी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिससे वर्ष 2015-16 से रद्द किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या बढ़कर 70 हो गई। 94.3 प्रतिशत रद्दीकरण गैर-अनुसूचित श्रेणी में हुए (चार्ट V.4बी)।

V.9 शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री एन.एस.विश्वनाथन) की सिफारिशों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2022-23 में यूसीबी के लिए चार-स्तरीय विनियामक ढांचे को अपनाया।[4] मार्च 2024 के अंत में, टियर 1 में यूसीबी के शेयर में गिरावट आई जबकि टियर 2 की हिस्सेदारी वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) बढ़ी, जो आंशिक रूप से बढ़ते जमाराशियों के आधार को दर्शाती है। टियर 3 यूसीबी, यूसीबी की कुल संख्या में लगभग 5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, जमा, अग्रिम और कुल आस्तियों में एक तिहाई से अधिक हिस्सेदारी के साथ इस क्षेत्र पर हावी है (सारणी V.2)।

3.1. तुलन-पत्र

V.10 वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी के समेकित तुलन-पत्र ने 4 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष में 2.3 प्रतिशत से अधिक थी। एससीबी के सापेक्ष यूसीबी के तुलन-पत्र का आकार लगातार सातवें वर्ष गिरकर मार्च 2024 के अंत में 2.5 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2017 के अंत में 3.8 प्रतिशत था, जो देयताओं में जमा वृद्धि में कमी और आस्तियों के पक्ष पर ऋण के कारण कम हुआ (चार्ट V.5)।

चार्ट V.5: आस्ति में वृद्धि

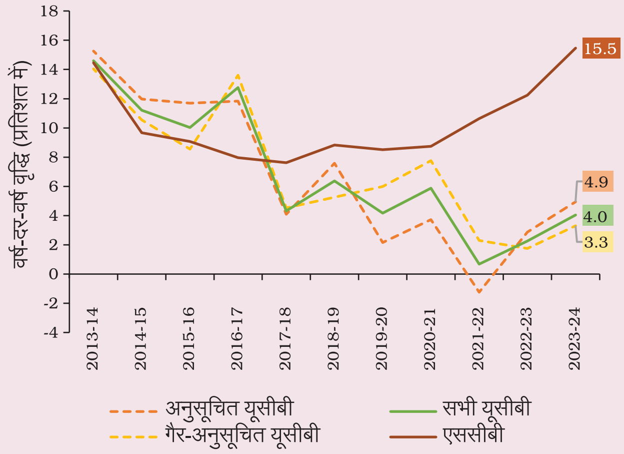

टिप्पणी : एससीबी के लिए, वर्ष 2023-24 के निजी क्षेत्र के बैंक डेटा में एक गैर-बैंक का निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय शामिल है और इसलिए, डेटा विलय से पहले पिछली अवधि के साथ तुलनीय नहीं हो सकता है।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई और सभी संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

V.11 सभी यूसीबी की जमा वृद्धि ने वर्ष 2023-24 के दौरान 4.1 प्रतिशत तक मामूली वृद्धि प्रदर्शित की, जो एससीबी में

सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण
(मार्च 2024 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में, प्रतिशत में शेयर)

टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमाराशियाँ		अग्रिम		कुल आस्तियां	
	संख्या	शेयर	राशि	शेयर	राशि	शेयर	राशि	शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	850	57.7	63,627	11.5	41,842	12.1	88,669	12.5
2	538	36.5	1,71,039	30.8	1,03,498	29.8	2,17,142	30.7
3	78	5.3	1,93,105	34.8	1,16,143	33.5	2,39,240	33.8
4	6	0.4	1,27,698	23.0	85,420	24.6	1,62,618	23.0
सभी यूसीबी	**1,472**	**100**	**5,55,469**	**100**	**3,46,903**	**100**	**7,07,669**	**100**

टिप्पणियाँ : 1. डेटा अनंतिम है।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण योग के बराबर नहीं हो सकता है।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

[4] ₹100 करोड़ रुपये तक जमाराशियों वाले यूसीबी को टियर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है; टियर 2 के रूप में जिनके पास ₹100 करोड़ से अधिक और ₹1,000 करोड़ तक जमा है; टियर 3 के रूप में जिनके पास ₹1,000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक जमा है; और ₹10,000 करोड़ से ऊपर वालों को टियर 4 में रखा गया है। 01 दिसंबर 2022 के परिपत्र के अनुसार, सभी यूसीबी इकाइयों और वेतनिक यूसीबी (जमाराशियों से अलग) को टियर 1 यूसीबी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त जमाराशियों की गणना तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को लेखापरीक्षित तुलन -पत्र के अनुसार की जाएगी।

चार्ट V.6: एससीबी की तुलना में यूसीबी का प्रदर्शन

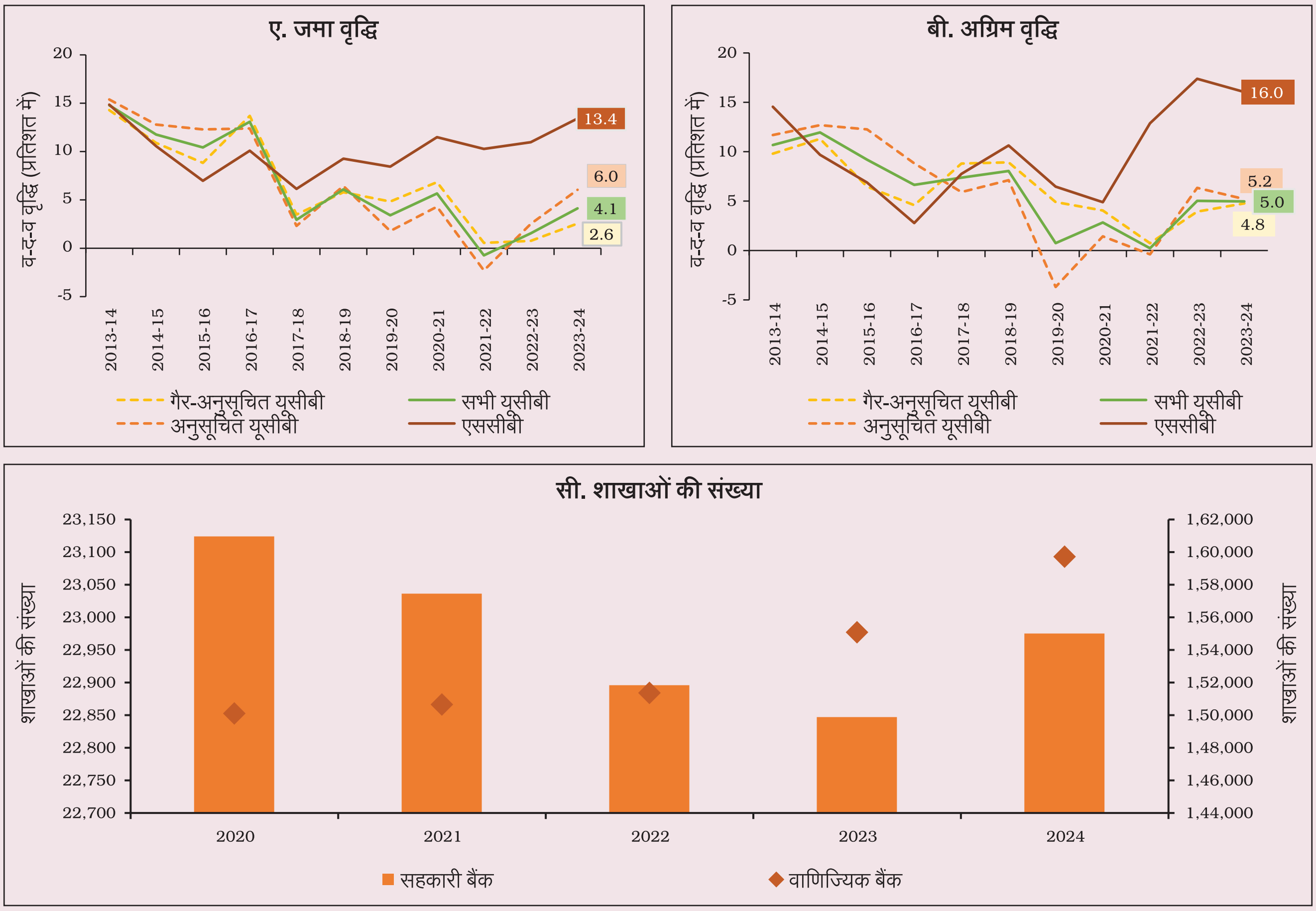

टिप्पणी: वर्ष 2023-24 के लिए एससीबी के जमा और अग्रिमों के डेटा में निजी क्षेत्र के बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत : ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई का सीआईएसबीआई पोर्टल और संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

13.4 प्रतिशत से नीचे रहा (चार्ट V.6ए)। यूसीबी के जमा में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में गति बनी रही। यूसीबी की ऋण वृद्धि वर्ष 2023-24 में 5.0 प्रतिशत पर धीमी रही, एससीबी द्वारा दर्ज 16.0 प्रतिशत के विस्तार के एक तिहाई से भी कम थी (सारणी V.3 और चार्ट V.6बी)। हालांकि, यूसीबी की ऋण वृद्धि सितंबर 2024 के अंत में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई। हाल के वर्षों में यूसीबी की जमा और ऋण वृद्धि एससीबी से पीछे रही जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यूसीबी की संख्या और उनके शाखा नेटवर्क में गिरावट परिलक्षित होती है (चार्ट V.6सी)। दूसरी ओर, एससीबी अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं।

V.12 यूसीबी का ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात वर्ष 2023-24 में लगातार तीसरे वर्ष बढ़कर 62.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.7)। मार्च 2024 के अंत में यूसीबी की कुल देयताओं में उधार का हिस्सा 0.8 प्रतिशत था, जो एससीबी के दसवें हिस्से (9.0 प्रतिशत) से भी कम था।

V.13 आस्तियों और जमाराशियों के संदर्भ में यूसीबी की संख्या का वितरण पिछले कुछ वर्षों बढ़ोतरी की ओर रहा है और द्वि-मोडल से एकल-मोडल में बदल गया है (चार्ट V.8)। वर्ष 2014-15 में, 40 प्रतिशत से अधिक यूसीबी ₹25 करोड़

सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी (प्रतिशत में व-द-व वृद्धि)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएँ								
1) पूंजी	4,256 (1.4)	4,293 (1.3)	10,459 (2.8)	10,831 (2.8)	14,715 (2.2)	15,124 (2.1)	3.2	2.8
2) आरक्षित निधि और अधिशेष	22,287 (7.3)	25,298 (7.9)	25,958 (6.9)	29,435 (7.6)	48,245 (7.1)	54,732 (7.7)	12.7	13.4
3) जमाराशियाँ	2,39,982 (78.3)	2,54,479 (79.1)	2,93,484 (78.6)	3,00,991 (78.0)	5,33,466 (78.4)	5,55,469 (78.5)	1.5	4.1
4) उधार	5,776 (1.9)	5,082 (1.6)	465 (0.1)	297 (0.1)	6,241 (0.9)	5,380 (0.8)	10.3	-13.8
5) अन्य देयताएं और प्रावधान	34,280 (11.2)	32,571 (10.1)	43,250 (11.6)	44,392 (11.5)	77,530 (11.4)	76,963 (10.9)	0.5	-0.7
आस्तियां								
1) हाथ में नकदी	1660 (0.5)	1759 (0.5)	4224 (1.1)	4434 (1.1)	5884 (0.9)	6193 (0.9)	-6.4	5.3
2) आरबीआई के पास शेष राशि	12,770 (4.2)	13,778 (4.3)	3,592 (1.0)	4,545 (1.2)	16,362 (2.4)	18,323 (2.6)	-0.4	12.0
3) बैंकों के पास शेष राशि	21,011 (6.9)	24,701 (7.7)	45,718 (12.2)	47,715 (12.4)	66,729 (9.8)	72,415 (10.2)	-4.9	8.5
4) कॉल और अल्प सूचना पर मुद्रा	2,554 (0.8)	2,367 (0.7)	886 (0.2)	919 (0.2)	3,440 (0.5)	3,286 (0.5)	-31.1	-4.5
5) निवेश	83,254 (27.2)	86,626 (26.9)	1,07,412 (28.7)	1,07,188 (27.8)	1,90,666 (28.0)	1,93,814 (27.4)	1.6	1.7
6) ऋण और अग्रिम	1,51,663 (49.5)	1,59,553 (49.6)	1,78,828 (47.9)	1,87,350 (48.5)	3,30,491 (48.6)	3,46,903 (49.0)	5.0	5.0
7) अन्य आस्तियां	33,668 (11.0)	32,939 (10.2)	32,957 (8.8)	33,795 (8.8)	66,625 (9.8)	66,734 (9.4)	2.4	0.2
कुल देयताएं/आस्तियां	**3,06,581 (100)**	**3,21,723 (100)**	**3,73,616 (100)**	**3,85,946 (100)**	**6,80,197 (100)**	**7,07,669 (100)**	**2.3**	**4.0**

टिप्पणियां: 1. 2024 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं / आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण योग के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

से ₹50 करोड़ और ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ की आस्ति श्रेणियों में थे; वर्ष 2023-24 में, 44.3 प्रतिशत यूसीबी ₹50 करोड़ से ₹250 करोड़ की आस्ति श्रेणियों में थे। अग्रिमों के संदर्भ में, मार्च 2024 के अंत में मॉडल वर्ग ₹25 करोड़ से ₹50

चार्ट V.7: ऋण-जमा अनुपात: यूसीबी *बनाम* एससीबी
(मार्च के अंत में)

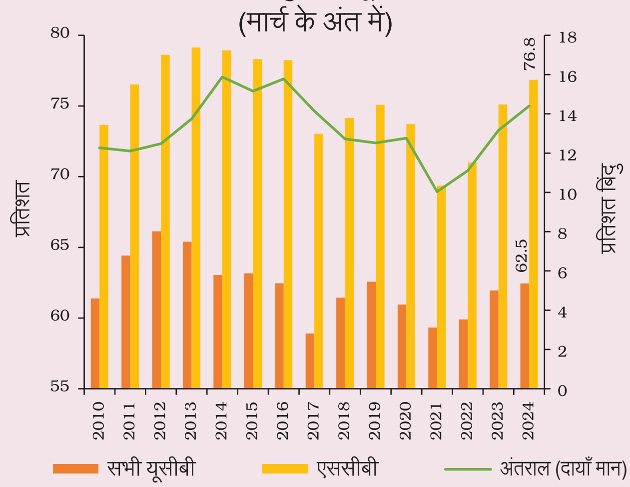

टिप्पणी: मार्च 2024 के एससीबी के डेटा में गैर-बैंक के निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई और संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

चार्ट V.8 : आस्तियों के आकार के अनुसार यूसीबी का विभाजन

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.4: जमाराशि, अग्रिम और आस्तियों के अनुसार यूसीबी का विभाजन
(मार्च 2024 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	जमाराशियां		अग्रिम		आस्तियां	
	यूसीबी की संख्या	राशि	यूसीबी की संख्या	राशि	यूसीबी की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
0 ≤ X < 10	83	495	183	1,093	40	251
10 ≤ X < 25	164	2,914	241	4,096	118	2,072
25 ≤ X < 50	240	8,879	282	9,921	212	7,839
50 ≤ X < 100	300	21,543	258	18,084	308	22,489
100 ≤ X < 250	322	52,648	256	39,538	344	55,860
250 ≤ X < 500	156	55,565	135	47,284	199	70,093
500 ≤ X < 1000	116	79,450	65	45,585	132	92,885
1000 ≤ X	91	3,33,976	52	1,81,301	119	4,56,181
कुल	**1,472**	**5,55,469**	**1,472**	**3,46,903**	**1,472**	**7,07,669**

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. 'X' जमा, अग्रिम और आस्तियों की राशि को इंगित करता है।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.9 : निवेश : यूसीबी *बनाम* एससीबी

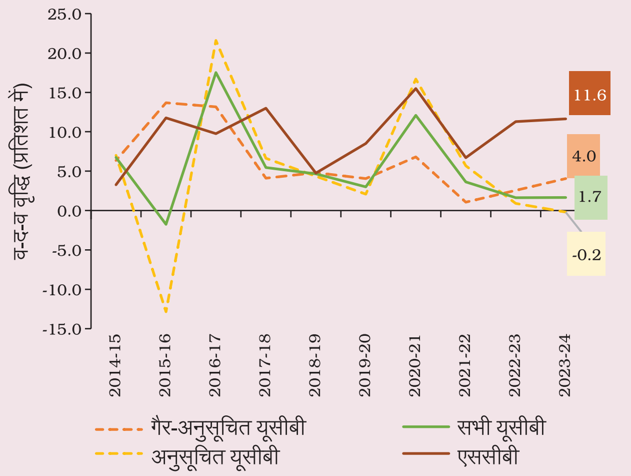

टिप्पणी: वर्ष 2023-24 के लिए एससीबी के डेटा में निजी क्षेत्र के बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत : ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई और संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

करोड़ था, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक यूसीबी के पास कुल अग्रिम ₹250 करोड़ से कम थे (सारणी V.4)।

V.14 वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी की निवेश वृद्धि काफी हद तक अपरिवर्तित रही, जिससे एससीबी के साथ अंतर और बढ़ गया (चार्ट V.9)।

V.15 यूसीबी का 90 प्रतिशत निवेश एसएलआर लिखतों में रहा, जबकि एससीबी का 83 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में यूसीबी के एसएलआर निवेश कम हुए (सारणी V.5)। पिछले कुछ वर्षों में, यूसीबी के कुल एसएलआर निवेशों में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है।

3.2. वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता

V.16 वर्ष 2023-24 के दौरान यूसीबी के परिचालन लाभ में गिरावट आई क्योंकि कुल व्यय कुल आय की तुलना में तेज गति से बढ़ा। हालांकि निवल लाभ (कर से पहले और बाद) बेहतर आस्ति गुणवत्ता के कारण प्रावधानों और आकस्मिकताओं में

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

	बकाया राशि (मार्च के अंत में)			घट-बढ़ (%)	
	2022	2023	2024	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
कुल निवेश (ए + बी)	1,87,612 (100.0)	1,90,666 (100.0)	1,93,814 (100.0)	1.6	1.7
ए. एसएलआर निवेश (i से iii)	1,67,802 (89.4)	1,71,715 (90.1)	1,74,352 (90.0)	2.3	1.5
(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	1,04,762 (55.8)	1,06,716 (56.0)	1,06,223 (54.8)	1.9	-0.5
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	62,613 (33.4)	64,695 (33.9)	67,741 (35.0)	3.3	4.7
(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	427 (0.2)	304 (0.2)	388 (0.2)	-28.8	27.6
बी. गैर-एसएलआर निवेश	19,809 (10.6)	18,951 (9.9)	19,462 (10.0)	-4.3	2.7

टिप्पणियां: 1. 2024 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल निवेश (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण योग के बराबर नहीं हो सकता है।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹करोड़ में)

	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी घट-बढ़ (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. कुल आय [i+ii]	**22,460 (100.0)**	**24,172 (100.0)**	**29,921 (100.0)**	**31,054 (100.0)**	**52,381 (100.0)**	**55,226 (100.0)**	**1.8**	**5.4**
i. ब्याज आय	19,473 (86.7)	21,476 (88.8)	28,125 (94.0)	29,232 (94.1)	47,598 (90.9)	50,708 (91.8)	2.1	6.5
ii. गैर-ब्याज आय	2,987 (13.3)	2,696 (11.2)	1,796 (6.0)	1,821 (5.9)	4,783 (9.1)	4,518 (8.2)	-0.8	-5.5
बी. कुल व्यय [i+ii]	**17,820 (100.0)**	**19,785 (100.0)**	**24,592 (100.0)**	**25,999 (100.0)**	**42,411 (100.0)**	**45,784 (100.0)**	**-0.5**	**8.0**
i. ब्याज व्यय	11,093 (62.3)	12,838 (64.9)	16,382 (66.6)	17,451 (67.1)	27,475 (64.8)	30,289 (66.2)	-4.3	10.2
ii. गैर-ब्याज व्यय	6,727 (37.7)	6,947 (35.1)	8,209 (33.4)	8,548 (32.9)	14,936 (35.2)	15,495 (33.8)	7.5	3.7
जिनमें से: स्टाफ व्यय	2,955	2,999	4,259	4,370	7,214	7,368	2.7	2.1
सी. लाभ								
i. परिचालन लाभ की राशि	4,641	4,387	5,329	5,055	9,970	9,441	12.9	-5.3
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	2,899	1,200	2,671	1,904	5,570	3,104	15.9	-44.3
iii. करों के लिए प्रावधान	468	751	852	858	1,319	1,609	16.9	21.9
iv. करों से पहले निवल लाभ की राशि	1,742	3,187	2,658	3,151	4,400	6,338	9.3	44.0
v. करों के बाद निवल लाभ की राशि	1,274	2,435	1,807	2,293	3,080	4,729	6.4	53.5

टिप्पणियां: 1. 2023-24 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल आय/व्यय (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण योग के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

गिरावट होने की वजह से था। लाभांश आय में गिरावट, अचल आस्तियों की बिक्री में हानि और विदेशी मुद्रा परिचालन पर कम लाभ के कारण गैर-ब्याज आय में गिरावट आई। आंशिक रूप से कर्मचारियों के खर्चों में कमी के कारण यूसीबी के गैर-ब्याज व्यय की वृद्धि में कमी आई (सारणी V.6 और परिशिष्ट सारणी V.1)। कुल आय में गैर-ब्याज आय का हिस्सा बड़े एसयूसीबी में अधिक था और उनकी लाभप्रदता से विपरीत रूप से संबंधित था (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में गैर-ब्याज आय के निर्धारक

जबकि ब्याज आय बैंकिंग गतिविधि का मूल है, गैर-ब्याज आय के माध्यम से विविधीकरण उच्च जोखिम-समायोजित लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है (अहमद, 2017)।

भारत में एसयूसीबी की कुल आय में गैर-ब्याज आय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 10.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 16.7 प्रतिशत हो गई थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 13.3 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए 47 एसयूसीबी के वार्षिक पैनल डेटा का उपयोग करते हुए, कुल आय में गैर-ब्याज आय के हिस्से के निर्धारकों का पता लगाने के लिए दो निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन मॉडल का अनुमान लगाया गया है। बैंक विशिष्ट व्याख्यात्मक चर जैसे आस्ति का आकार, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और आय और लागत अनुपात और समष्टिआर्थिक नियंत्रण चर (नाममात्र जीडीपी वृद्धि) को मॉडल I में शामिल किया गया है। मॉडल II में, गैर-ब्याज आय के हिस्से पर टियर 4 एसयूसीबी की लाभप्रदता के अंतर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक इंटरैक्शन डमी [डमी टियर 123 * आरओए (-1)] लाया गया है। डमी टियर123 ₹10,000 करोड़ से कम के जमा आधार वाले एसयूसीबी *अर्थात*, टियर 1 से 3 एसयूसीबी के लिए मान 1 लेता है और टियर 4 एसयूसीबी (जमा > ₹ 10,000 करोड़) के लिए मान 0 लेता है।

प्रतिगमन अनुमानों से संकेत मिलता है कि बड़े आस्ति आकार वाले एसयूसीबी के पास गैर-ब्याज आय का अधिक हिस्सा है। उच्च लाभप्रदता (आरओए) गैर-ब्याज आय के हिस्से को कम करती है (सारणी V.1.1)। इसके अलावा, जैसे-जैसे लाभप्रदता बढ़ती है, टियर 4 एसयूसीबी के सापेक्ष टियर 1 से 3 एसयूसीबी के लिए गैर-ब्याज आय का हिस्सा बढ़ जाता है (मॉडल II)। कुल मिलाकर, अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि जैसे-जैसे बैंक आकार में बढ़ते हैं, वे गैर-पारंपरिक गतिविधियों की ओर विविधता लाने में सक्षम होते हैं जो उनकी गैर-ब्याज आय को बढ़ाता है।

(जारी...)

सारणी V.1.1: एसयूसीबी की गैर-ब्याज आय के निर्धारक

व्याख्यात्मक चर	गैर-ब्याज आय का हिस्सा	गैर-ब्याज आय का हिस्सा
	(1)	(2)
गैर-ब्याज आय का हिस्सा (-1)	0.00361 (0.128)	0.00193 (0.128)
जीडीपी वृद्धि दर	-0.119* (0.0606)	-0.117* (0.0603)
लागत और आय अनुपात (-1)	-3.143 (6.719)	-3.235 (6.720)
कुल आस्ति लॉग (-1)	4.285*** (1.551)	4.613*** (1.599)
आरओए (-1)	-0.431* (0.243)	-2.953** (1.428)
डमी टियर123*आरओए (-1)		2.522* (1.392)
स्थिरांक	-19.09 (15.36)	-21.45 (15.60)
किए गए अवलोकन	376	376
आर- वर्गित	0.513	0.514

टिप्पणीयां: 1. कोष्ठक में मजबूत मानक त्रुटियां हैं।
2. *** पी<0.01, ** पी<0.05, * पी<0.1
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

संदर्भ:

अहमद, एमएम (2017)। आस्ति गुणवत्ता, गैर-ब्याज आय और बैंक लाभप्रदता: भारतीय बैंकों से साक्ष्य, आर्थिक मॉडलिंग, 63, 1-14.

V.17 वर्ष 2023-24 में उच्च निवल लाभ को दर्शाते हुए, यूसीबी के आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), इक्विटि पर प्रतिलाभ (आरओई) और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार हुआ। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में, यूसीबी की लाभप्रदता और बढ़ी (सारणी V.7)।

V.18 यूसीबी की लाभप्रदता, जो वर्ष 2019-20 में एक बड़े यूसीबी की हानि के कारण कम हो गई थी, तब से आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ ठीक हो गई है (चार्ट V.10ए और बी)।

सारणी V.7: यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक

(प्रतिशत)

	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	सितं-24
1	2	3	4	5	6	7	8
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.42	0.78	0.49	0.60	0.46	0.68	0.84
इक्विटि पर प्रतिलाभ	5.08	8.68	5.17	5.98	5.13	7.12	8.4
निवल ब्याज मार्जिन	2.77	3.35	3.17	4.02	2.99	3.70	3.42

टिप्पणी: 2023-24 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

3.3. सुदृढ़ता

V.19 सहकारी बैंकों (यूसीबी सहित) पर जुर्माना लगाने के मामलों की संख्या 22 प्रतिशत बढ़कर पिछले वर्ष के 176 से वर्ष 2023-24 के दौरान 215 हो गई। हालांकि, जुर्माने की राशि में 13.8 प्रतिशत की गिरावट आई (अध्याय IV में सारणी IV.16)। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1,432 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया, जो पूरी तरह से परिसमापन/सभी समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए सहकारी बैंकों से संबंधित थे।

3.4. पूंजी पर्याप्तता

V.20 जुलाई 2022 में, यूसीबी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे ने टियर 2 से टियर 4 यूसीबी के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया, जबकि इसे टियर 1 यूसीबी के लिए 9 प्रतिशत पर रखा। मार्च 2024 के अंत में, 42.3 प्रतिशत यूसीबी ऊपरी टियर (टियर 2 से

चार्ट V.10: लाभप्रदता संकेतक: यूसीबी *बनाम* एससीबी
(मार्च के अंत में)

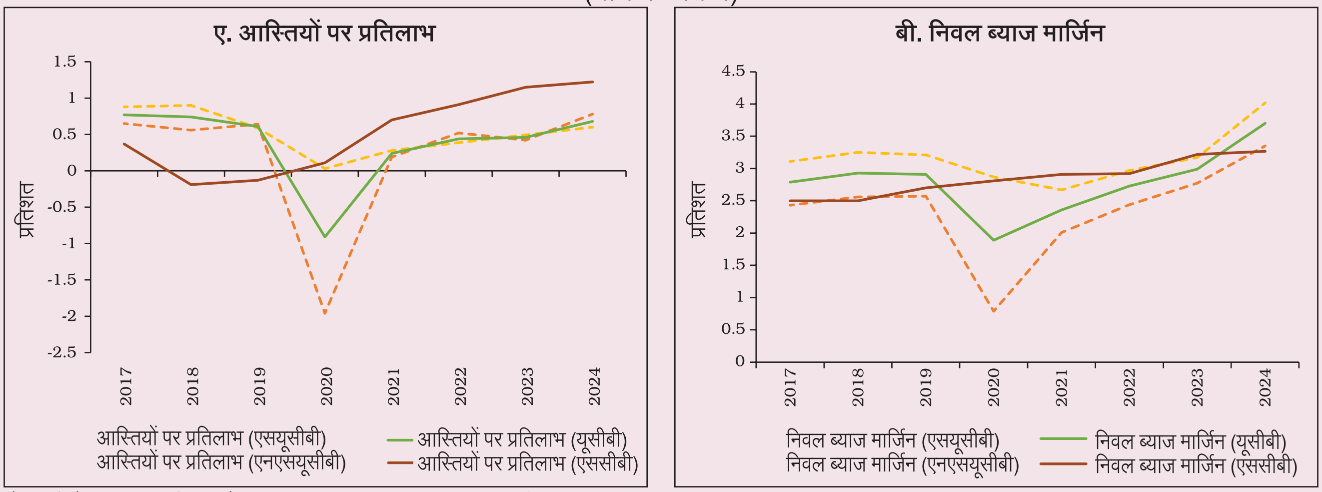

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियाँ, आरबीआई।

टियर 4) से संबंधित थे, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक ने 12 प्रतिशत से ऊपर सीआरएआर बनाए रखा (सारणी V.8 और परिशिष्ट सारणी V.2)।

V.21 वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी के समेकित सीआरएआर में उच्च टियर I पूंजी के कारण सुधार हुआ, जो *अन्य बातों के साथ-साथ* प्रावधानों में कमी और टियर I पूंजी में पुनर्मूल्यन रिज़र्व[5] (पहले टियर II पूंजी के रूप में जाना जाता था, उन्हें मार्च 2023 के अंत से कुछ शर्तों के अधीन टियर I पूंजी के रूप में अनुमति दी गई) को शामिल करने की विनियामक अनुमति के कारण लाभप्रदता में वृद्धि से प्रेरित था (सारणी V.9)।

सारणी V.8: सीआरएआर-वार यूसीबी का विभाजन
(मार्च 2024 के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर-अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	1	28	29
3 <= सीआरएआर < 6	1	13	14
6 <= सीआरएआर < 9	0	14	14
9 <= सीआरएआर < 12	2	85	87
12 <= सीआरएआर	45	1,283	1328
कुल	**49**	**1,423**	**1,472**

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

इसके अतिरिक्त, यूसीबी द्वारा दीर्घकालिक गौण बॉण्ड जुटाने के प्रयासों ने उनके पूंजी आधार को मजबूत किया।

V.22 वर्ष 2021-22 के बाद से पूंजी में तेज वृद्धि को दर्शाते हुए, यूसीबी का सीआरएआर मार्च 2024 के अंत में एससीबी की तुलना में अधिक था (चार्ट V.11)। सीआरएआर सितंबर 2024 के अंत में 17.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

चार्ट V.11 : सीआरएआर : यूसीबी *बनाम* एससीबी
(मार्च अंत में)

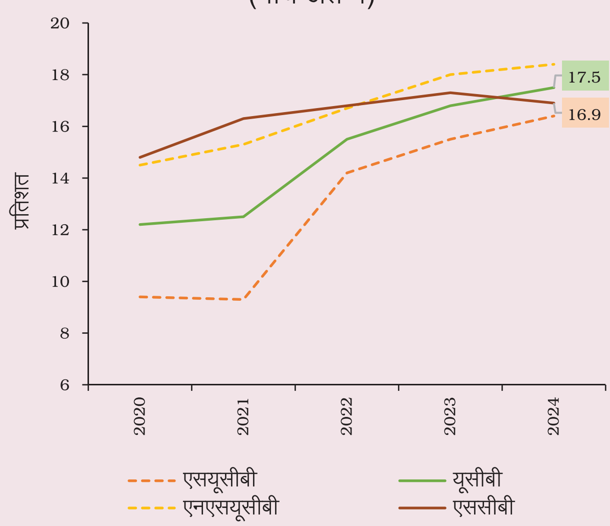

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

[5] पुनर्मूल्यन रिज़र्व को पहले टियर II पूंजी के रूप में माना जाता था, लेकिन मार्च 2023 के अंत से कुछ शर्तों के अधीन, इसे टियर I पूंजी के रूप में अनुमति दी गई।

सारणी V.9: यूसीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

		अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**पूंजीगत निधि**	**23,367**	**25,964**	**30,715**	**33,238**	**54,081**	**59,202**
	i) टियर 1 पूंजी	18,016	20,125	26,762	29,086	44,778	49,210
	ii) टियर 2 पूंजी	5,351	5,839	3,953	4,152	9,304	9,992
2	**जोखिम-भारित आस्तियां**	**1,50,776**	**1,57,866**	**1,70,247**	**1,80,672**	**3,21,024**	**3,38,538**
3	**सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)**	**15.5**	**16.4**	**18.0**	**18.4**	**16.8**	**17.5**
	जिनमें से:						
	टियर I	11.9	12.7	15.7	16.1	13.9	14.5
	टियर II	3.5	3.7	2.3	2.3	2.9	3.0

टिप्पणी: 2024 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

3.5. आस्ति गुणवत्ता

V.23 सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के अनुपात द्वारा मापी गई शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में लगातार तीसरे वर्ष सुधार हुआ, हालांकि यह एससीबी से काफी अधिक है (चार्ट V.12ए)। सितंबर 2024 के अंत में, यूसीबी का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2023 के अंत में 10.9 प्रतिशत की तुलना में 9.6 प्रतिशत था। यूसीबी में, एनएसयूसीबी का जीएनपीए अनुपात अधिक था। जैसे-जैसे जीएनपीए में गिरावट गिरते प्रावधानों से आगे निकल गई, प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार हुआ और मानक अग्रिमों[6] के लिए यूसीबी के प्रावधानीकरण मानदंडों के चरणबद्ध सामंजस्य के साथ इसमें और वृद्धि होने की संभावना है (सारणी V.10)।

V.24 मार्च 2024 के अंत में, बड़े उधार खाते, *यानी,* ₹5 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले खाते, यूसीबी के कुल ऋण का 24.3 प्रतिशत और उनके जीएनपीए का 31.1 प्रतिशत थे। इन खातों ने एसयूसीबी और एनएसयूसीबी के बीच भिन्न व्यवहार प्रदर्शित किए। एसयूसीबी के ऋण का 43 प्रतिशत इन खातों में केंद्रित था, जबकि इन उधारकर्ताओं के लिए एनएसयूसीबी का एक्सपोजर 10 प्रतिशत से कम था। बड़े उधारकर्ताओं की एनएसयूसीबी के एनपीए में 15.3 प्रतिशत और एसयूसीबी के एनपीए में 63.0 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। पूरे क्षेत्र के लिए, विशेष उल्लेख खाते-1 (एसएमए-1) में वर्ष के दौरान गिरावट आई लेकिन एसएमए-2 में वृद्धि हुई, जिसका कारण मुख्य रूप से एसयूसीबी रहा (चार्ट V.12बी)।

3.6. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

V.25 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में यूसीबी के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाना है[7]। मार्च 2023 के अंत और मार्च 2024 के अंत का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक

सारणी V.10: यूसीबी की अनर्जक आस्तियां
(मार्च के अंत में)

	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
सकल एनपीए (₹ करोड़)	10,016	8,422	19,188	16,988	29,204	25,411
सकल एनपीए अनुपात (%)	6.6	5.3	10.7	9.1	8.8	7.3
निवल एनपीए (₹ करोड़)	2,298	1,960	4,386	1,953	6,684	3,913
निवल एनपीए अनुपात (%)	1.6	1.3	2.7	1.1	2.2	1.2
प्रावधानीकरण (₹ करोड़)	7,718	6,462	14,802	15,035	22,520	21,497
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	77.1	76.7	77.1	88.5	77.1	84.6

टिप्पणी: 2024 के लिए: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

6 पूर्ववर्ती टियर I यूसीबी, जो 'उपर्युक्त को छोड़कर अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों' पर 0.25 प्रतिशत का मानक आस्ति प्रावधान बनाए हुए थे, को प्रावधान आवश्यकता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक 0.30 प्रतिशत, 30 सितंबर 2024 तक 0.35 प्रतिशत और 31 मार्च 2025 तक 0.40 प्रतिशत तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

7 मार्च 2020 में जारी और जुलाई 2023 में संशोधित दिशानिर्देशों में यूसीबी को क्रमशः मार्च 2024, 2025 और 2026 के अंत तक अपने एएनबीसी या सीईओबीई के 60 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता है।

चार्ट V.12: आस्ति गुणवत्ता
(मार्च के अंत में)

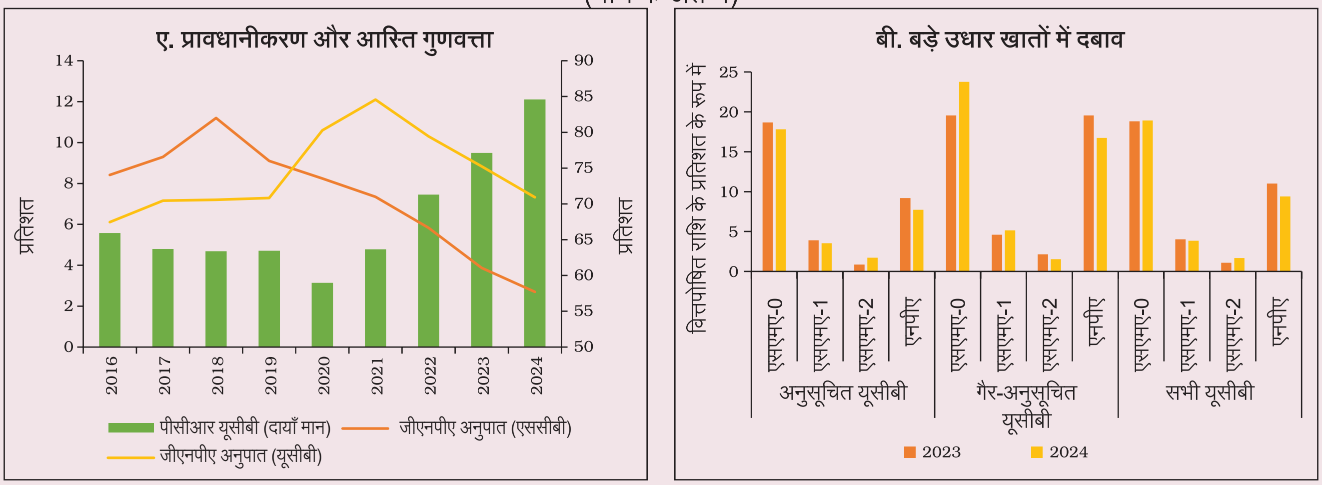

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई और बैंकों के वार्षिक खाते।

ऋण (एएनबीसी) या सीईओबीई का 60 प्रतिशत था। जबकि यूसीबी ने मार्च 2023 के अंत में आसानी से लक्ष्य पूरा कर लिया, वे मार्च 2024 के अंत में चूक गए (चार्ट V.13)।

V.26 वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में एमएसएमई, विशेष रूप से छोटे उद्यमों की हिस्सेदारी में गिरावट आई। सूक्ष्म उद्यमों को यूसीबी का ऋण 7.5 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गया। हालांकि कमजोर वर्गों को ऋण देने में गिरावट आई, यूसीबी ने 11.5 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा किया। कुल अग्रिमों में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा (सारणी V.11)।

चार्ट V.13: प्राथमिकता क्षेत्र उधार
(मार्च के अंत में)

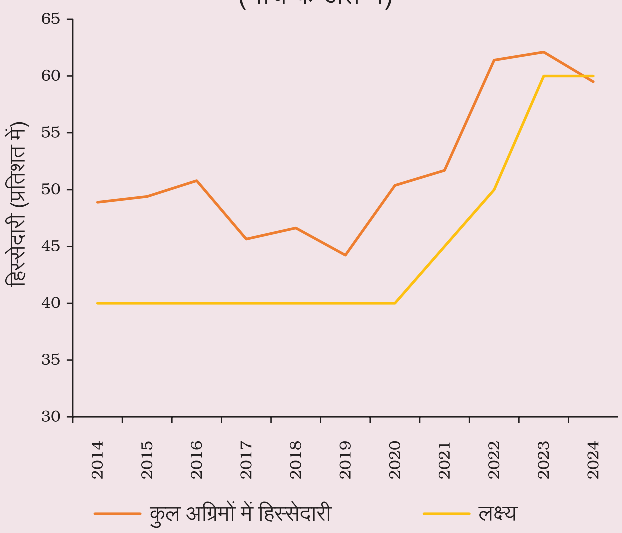

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

4. ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.27 ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां (आरसीसी) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए पर्याप्त और किफायती ऋण प्रदान करने के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में अस्तित्व में आईं। वे भीतरी इलाकों में अपनी जमीनी स्तर की उपस्थिति के कारण ग्रामीण ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आरसीसी अपने शहरी समकक्षों से उनके परिचालन के क्षेत्र, पहुंच, प्रदर्शन और देयताओं की संरचना के संदर्भ में भिन्न होती हैं। मार्च 2024 के अंत में, 2,140 शाखाओं के साथ 34 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), 13,759 शाखाओं के साथ 351 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)[8] थे। मार्च 2023 के अंत में, 6.5 लाख गांवों में फैली 1,06,955 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) और दीर्घावधिक आरसीसी में 692 शाखाओं के साथ 13 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और

[8] इसमें जम्मू और कश्मीर में 3 डीसीसीबी शामिल हैं जिन्हें अभी लाइसेंस दिया जाना है और इसमें तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि शामिल नहीं है जिसे केवल विनियमन/पर्यवेक्षण के प्रयोजनों के लिए डीसीसीबी माना जाता है।

सारणी V.11 : यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण की संरचना
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	2023		2024	
	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)
1 2	3	4	5	6
1 कृषि [(i)+(ii)+(iii)]	15,404	4.7	16,329	4.7
(i) कृषि ऋण	11,470	3.5	12,328	3.6
(ii) कृषि अवसंरचना	902	0.3	1,224	0.4
(iii) सहायक गतिविधियाँ	3,032	0.9	2,777	0.8
2 सूक्ष्म और लघु उद्यम (i) + (ii) + (iii) + (iv)]	1,24,658	37.7	1,29,069	37.2
(i) सूक्ष्म उद्यम	52,849	16.0	56,533	16.3
(ii) लघु उद्यम	48,903	14.8	48,495	14.0
(iii) मध्यम उद्यम	22,281	6.7	23,492	6.8
(iv) केवीआई को अग्रिम ('एमएसएमई के लिए अन्य वित्त' सहित)	625	0.2	549	0.2
3 निर्यात ऋण	319	0.1	723	0.2
4 शिक्षा	3,187	1.0	3,226	0.9
5 आवास	29,286	8.9	29,268	8.4
6 सामाजिक अवसंरचना	1,151	0.3	1,038	0.3
7 नवीकरणीय ऊर्जा	972	0.3	1,419	0.4
8 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत 'अन्य' श्रेणी	30,121	9.1	25,326	7.3
9 **कुल (1 to 8)**	2,05,269	62.1	2,06,399	59.5
जिनमें से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कमजोर वर्गों को ऋण	45,565	13.8	42,743	12.3

टिप्पणियाँ 1. वर्ष 2024 के लिए डेटा अनंतिम हैं।
2. प्रतिशत यूसीबी के कुल ऋण से संबंधित हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

608 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) थे।

V.28 जबकि यूसीबी मुख्य रूप से धन जुटाने के लिए जमाराशियों पर निर्भर रहते हैं, आरसीसी उधार पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। मार्च 2023 के अंत में जमा राशि यूसीबी की कुल देयताओं का 78.4 प्रतिशत थी, जबकि आरसीसी के लिए यह 54.2 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, मार्च 2023 के अंत में उधार आरसीसी की कुल देयताओं का लगभग 33 प्रतिशत और यूसीबी की देयताओं का 1 प्रतिशत से भी कम था।

V.29 यूसीबी के स्वामित्व वाली निधियों[9] और देयताओं का अनुपात समय के साथ बढ़ा है और मार्च 2023 के अंत में आरसीसी से आगे निकल गया है, क्योंकि यूसीबी के पास अधिक रिज़र्व है। आरसीसी में, एससीएआरडीबी के पास कुल देयताओं में स्वामित्व वाली निधियों का सबसे अधिक हिस्सा है (चार्ट V.14ए)। यूसीबी की आस्ति गुणवत्ता आरसीसी से बेहतर रही, जबकि दीर्घकालिक सहकारी समितियों के जीएनपीए अनुपात में गिरावट के कारण आरसीसी में गिरावट आई (चार्ट V.14बी)।

V.30 वर्ष 2022-23 में उन आरसीसी ने जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक संस्थान शामिल हैं अपने परिचालन का और

चार्ट V.14 : आरसीसी *बनाम* यूसीबी : तुलन पत्र और आस्ति गुणवत्ता संकेतक
(मार्च के अंत में)

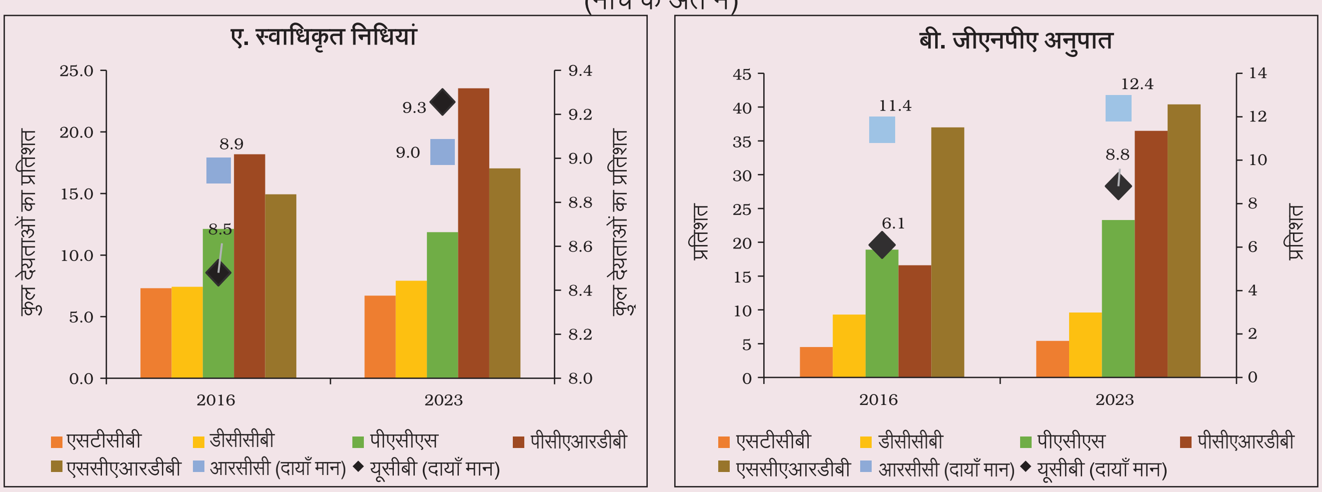

स्रोत : आरबीआई, नाबार्ड, एनएएफ़एससीओबी।

[9] स्वामित्व वाले फंड में पूंजी और रिज़र्व और अधिशेष शामिल हैं।

विस्तार किया। सहकारी क्षेत्र (शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियों को मिलाकर) की कुल आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी एक वर्ष पहले के 69.2 प्रतिशत से बढ़कर 70.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट V.15)।

V.31 आरसीसी में, अल्पकालिक संस्थान किसानों और ग्रामीण कारीगरों को फसल ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करते हैं। दीर्घकालिक सहकारी समितियां - एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी - कृषि में निवेश के लिए निधियाँ प्रदान करती हैं, जिसमें भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण और लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग और आवास शामिल हैं। एससीएआरडीबी प्रत्यक्ष ऋण के लिए नाबार्ड जैसी संस्थाओं से तथा पीसीएआरडीबी के माध्यम से ऋण लेते हैं। आरसीसी क्षेत्र में अल्पकालिक संस्थाओं का वर्चस्व है और कुल आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में बढ़कर 96.3 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2016 के अंत में 94.4 प्रतिशत थी (चार्ट V.16ए)। जबकि उधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ऋण सहकारी समितियों की निर्भरता यूसीबी की तुलना में अधिक है, दीर्घकालिक ऋण सहकारी समितियों का जमाकर्ता आधार विशेष रूप से छोटा है। अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों का वित्तीय प्रदर्शन उनके दीर्घकालिक समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर रहा है (चार्ट V.16बी)। कृषि,

चार्ट V.15: कुल सहकारी क्षेत्र में ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी

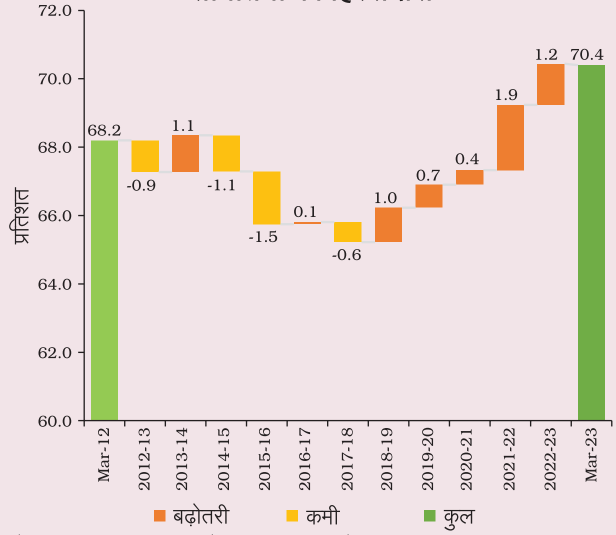

स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

अनर्जक आस्तियों, कम वसूली और उच्च परिचालन लागत पर केंद्रित गैर-विविध ऋण पोर्टफोलियो के कारण आरसीसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

V.32 पीएसीएस के कारण नीचे आने के बावजूद, आरसी क्षेत्र लगातार चौथे वर्ष लाभदायक रहा (सारणी V.12)। वर्ष 2022-23 में, आय में तेज वृद्धि (ब्याज और गैर-ब्याज दोनों) और कुल व्यय में कमी के कारण लाभ कमाने वाले पीसीएआरडीबी की संख्या में काफी वृद्धि हुई (चार्ट V.17)।

चार्ट V.16: दीर्घावधिक *बनाम* अल्पावधिक आरसीसी

(मार्च के अंत में)

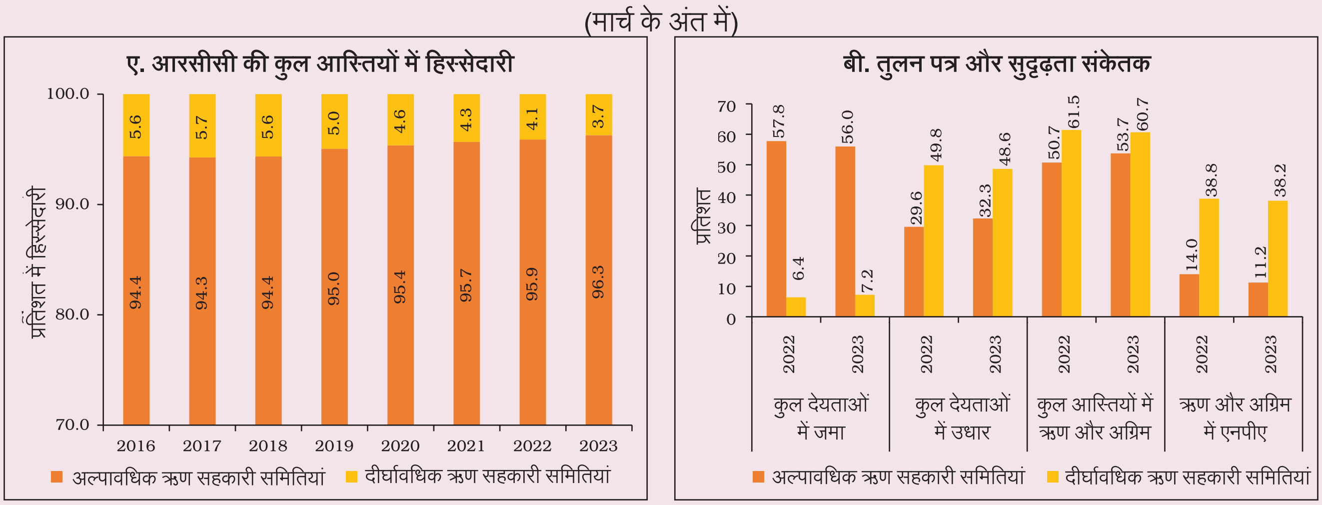

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफ़एससीओबी।

सारणी V.12: ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की प्रोफाइल
(मार्च 2023 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	अल्पवाधिक			दीर्घावधिक		ग्रामीण सहकारी बैंक	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी (पी)	पीसीएआरडीबी (पी)	मार्च-22	मार्च-23
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. सहकारी संस्थाओं की संख्या	34	351	1,06,955	13	608	1,05,268	1,07,961
बी. तुलन-पत्र संकेतक							
i. स्वामित्व वाली निधि (पूंजी + आरक्षित निधि)	30,318	55,216	48,565	6,545	5,527	1,35,460	1,46,171
ii. जमाराशियां	2,42,327	4,33,358	1,97,239	2,621	1,720	8,33,844	8,77,263
iii. उधार	1,54,970	1,47,207	2,01,329	12,559	16,712	4,55,373	5,32,778
iv. ऋण और अग्रिम	2,65,580	3,70,851	2,00,491	20,770	15,773	7,66,470	8,73,466
v. कुल देयताएं/आस्तियां	4,51,840	6,97,304	4,09,377^	27,794	32,445	14,98,292	16,18,761
सी. वित्तीय प्रदर्शन							
i. लाभ में संस्थान							
ए. संख्या	32	305	47,794	10	351	48,461	48,492
बी. लाभ की राशि	2,517	2,879	2,142	448	525	6,754	8,512
ii. हानि में संस्थान							
ए. संख्या	2	46	37,357	3	252	39,081	37,660
बी. हानि की राशि	60	998	3,586	40	305	5,506	4,989
iii. कुल लाभ (+)/हानि (-)	2,458	1,881	-1,444	408	220	1,248	3,523
डी. अनर्जक आस्तियां							
i. राशि	14,296	35,722	44,042^^	7,571	6,371	1,16,718	1,08,002
ii. बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में	5.4	9.6	23.3	36.5	40.4	15.2	12.4
ई. मांग और ऋण वसूली अनुपात* (प्रतिशत)	91.7	76.5	78.9	42.8	39.1	-	-

टिप्पणियाँ: 1. (पी) - डेटा अनंतिम हैं।
2. *: यह अनुपात जून 2022 के अंत में वसूले गए बकाया एनपीए के हिस्से को दर्शाता है।
3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 608 रिपोर्ट किए गए पीसीएआरडीबी में से 603 के संबंध में डेटा उपलब्ध हैं।
4. ^: कार्यशील पूंजी।
5. ^^: कुल अतिदेय।

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफ़एससीओबी।

चार्ट V.17: लाभ में चल रही सहकारी समितियां
(मार्च के अंत में)

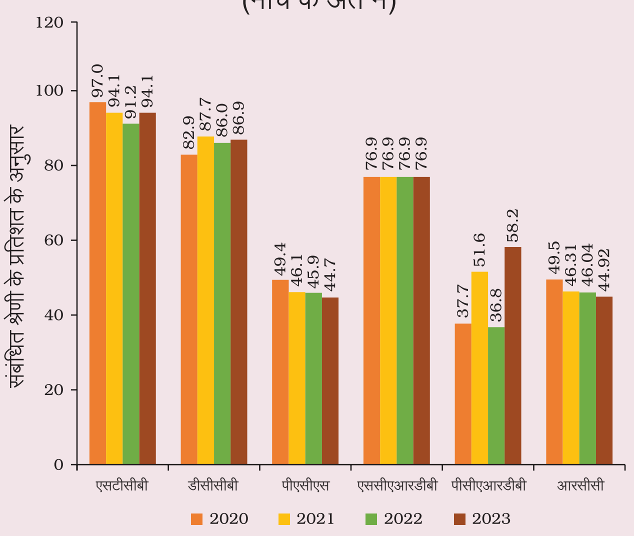

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफ़एससीओबी।

4.1. अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.33 अल्पकालिक आरसीसी - राज्य स्तर पर एसटीसीबी, जिला स्तर पर डीसीसीबी और ग्राम स्तर पर पीएसीएस - मुख्य रूप से डेयरी किसानों और मत्स्य इकाइयों की फसल ऋण और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समय के साथ, गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधि, और संबद्ध क्षेत्रों को मियादी ऋण देने और सूक्ष्मवित्त को शामिल करने की वजह से उनका दायरा बढ़ गया है। अल्पकालिक आरसीसी दो-, तीन- या मिश्रित-स्तरीय संरचना में काम करते हैं।[10] द्वि-स्तरीय संरचना में, एसटीसीबी अपनी शाखाओं के साथ-साथ पीएसीएस के माध्यम से भी उधार देते हैं। त्रि-स्तरीय संरचना में, एसटीसीबी सभी डीसीसीबी के लिए शीर्ष बैंक के रूप में काम करते हैं, जो मध्यवर्ती स्तर का

[10] 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में एक या एक से अधिक डीसीसीबी हैं और 15 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोई डीसीसीबी नहीं है और केवल दो-स्तरीय संरचना मौजूद है।

गठन करते हैं और संबद्ध समितियों को ऋण प्रदान करते हैं। मिश्रित संरचना वाले राज्यों में, एसटीसीबी कुछ जिलों में अपनी शाखाओं के माध्यम से और शेष जिलों में डीसीसीबी के माध्यम से काम करते हैं। जमा एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए धन का प्रमुख स्रोत है। दूसरी ओर, पीएसीएस उधार पर बहुत अधिक निर्भर है; पिछले कुछ वर्षों में जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आई है (चार्ट V.18)।

4.1.1. राज्य सहकारी बैंक

V.34 ग्रामीण सहकारी संरचना में शीर्ष संस्थान रखने वाले एसटीसीबी, विभिन्न कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। वे अन्य दो स्तरों को चलनिधि और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। उनके कुल ऋण पोर्टफोलियो में कृषि ऋण का हिस्सा 45 प्रतिशत से अधिक रहा।

तुलन-पत्र परिचालन

V.35 वर्ष 2023-24 में, एसटीसीबी के तुलन-पत्र लगातार चौथे वर्ष 8 प्रतिशत से अधिक बढ़े, जो आस्ति पक्ष पर ऋण और देयताओं के पक्ष पर उधार और जमा द्वारा संचालित हैं। मार्च 2024 के अंत में, सी-डी अनुपात मार्च 2023 के अंत में 109.6 प्रतिशत (एससीबी के मामले में 75.1 प्रतिशत) से बढ़कर 114.7 प्रतिशत (एससीबी के मामले में 76.8 प्रतिशत की तुलना में) हो गया। चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमा की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में घटकर 18.6 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2023 के अंत में 19.5 प्रतिशत थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज व्यय में वृद्धि हुई। जमा वृद्धि में सुधार हुआ लेकिन उधारों से कम रहा (सारणी V.13)।

चार्ट V.18: संसाधन संरचना: अल्पावधिक सहकारी समितियां
(मार्च के अंत में)

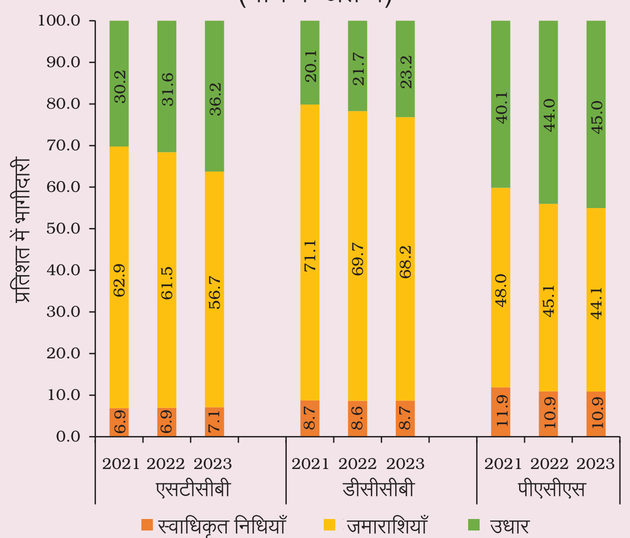

स्रोत : नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

V.36 अनुसूचित एसटीसीबी की ऋण वृद्धि वर्ष 2023-24 में कम हो गई, जबकि जमाराशि में पिछले वर्ष में कमी की तुलना में सुधार हुआ (सारणी V.14)।

लाभप्रदता

V.37 वर्ष 2023-24 के दौरान, एसटीसीबी के ब्याज व्यय की वृद्धि ब्याज आय से बढ़कर 24.9 प्रतिशत हो गई; उनकी निवल ब्याज आय (एनआईआई) में 5.7 प्रतिशत की गिरावट

सारणी V.13: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2023	2024पी	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	9,774 (2.2)	10,531 (2.2)	5.5	7.7
2. आरक्षित निधि	20,544 (4.5)	22,861 (4.7)	14.3	11.3
3. जमाराशियां	2,42,327 (53.6)	2,56,819 (52.6)	0.6	6.0
4. उधार	1,54,970 (34.3)	1,73,116 (35.5)	25.2	11.7
5. अन्य देयताएं	24,226 (5.4)	24,940 (5.1)	-4.1	2.9
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	21,237 (4.7)	22,661 (4.6)	12.6	6.7
2. निवेश	1,48,666 (32.9)	1,55,826 (31.9)	5.5	4.8
3. ऋण और अग्रिम	2,65,580 (58.8)	2,94,577 (60.3)	11.2	10.9
4. संचित हानि	1,348 (0.3)	1,146 (0.2)	-0.4	-15.0
5. अन्य आस्तियां	15,009 (3.3)	14,057 (2.9)	-12.4	-6.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**4,51,840 (100.00)**	**4,88,266 (100.00)**	**8.3**	**8.1**

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ प्रतिशत थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में संख्या ₹1 करोड़ तक पूर्णांकित की गई है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग समान नहीं हो सकता है।
4. पी: अनंतिम।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.14: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन पत्र संकेतक
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
जमाराशियां	1,87,456 (69.6)	1,97,751 (5.5)	2,11,784 (7.1)	2,04,432 (-3.5)	2,15,540 (5.4)
ऋण	1,94,310 (47.9)	2,06,322 (6.2)	2,28,194 (10.6)	2,55,750 (12.1)	2,78,147 (8.8)
एसएलआर निवेश	54,181 (63.5)	67,788 (25.1)	77,677 (14.6)	74,721 (-3.8)	77,525 (3.8)
क्रेडिट के साथ एसएलआर निवेश	2,48,492 (51.0)	2,74,110 (10.3)	3,05,871 (11.6)	3,30,471 (8.0)	3,55,671 (7.6)

टिप्पणियाँ: 1. डेटा संबंधित वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।
2. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर है।
स्रोत: आरबीआई अधिनियम की धारा 42 के तहत फॉर्म बी।

आई। तथापि, गैर-ब्याज आय में वृद्धि और परिचालन व्यय में कमी के कारण निवल लाभ में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी V.15)।

सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2022-23	2023-24 पी	घट-बढ़ प्रतिशत	
			2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. आय (i +ii)	**27,648 (100.00)**	**32,401 (100.00)**	**10.8**	**17.2**
i. ब्याज आय	26,654 (96.4)	30,974 (95.6)	10.3	16.2
ii. अन्य आय	994 (3.6)	1,427 (4.4)	26.9	43.6
बी. व्यय (i+ii+iii)	**25,191 (100.00)**	**29,710 (100.00)**	**11.1**	**17.9**
i. व्यय किए हुए ब्याज	19,043 (75.6)	23,793 (80.1)	15.1	24.9
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,920 (7.6)	1,979 (6.7)	-19.2	3.0
iii. परिचालन व्यय	4,227 (16.8)	3,938 (13.3)	12.7	-6.8
जिसमें से, मजदूरी विधेयक	2,060 (8.2)	2,077 (7)	-0.2	0.8
सी. लाभ				
i. निवल ब्याज आय	7,611	7,181	-0.3	-5.7
ii. परिचालन लाभ	3,990	4,205	35.4	5.4
iii. निवल लाभ	2,458	2,691	7.4	9.5

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ प्रतिशत थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में संख्या ₹1 करोड़ तक पूर्णांकित की गई है।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग समान नहीं हो सकता है।
4. पी: अनंतिम।
स्रोत: नाबार्ड।

V.38 94 प्रतिशत एसटीसीबी (यानी 34 में से 32 एसटीसीबी) ने वर्ष 2023-24 के दौरान लाभ दर्ज किया, जबकि यह वर्ष 2022-23 में 91 प्रतिशत था।[11] लाभ में पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र एसटीसीबी का प्रभुत्व था (चार्ट V.19 और परिशिष्ट सारणी V.3)।

आस्ति गुणवत्ता

V.39 एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार तीसरे वर्ष सुधार हुआ, जीएनपीए अनुपात मार्च 2021 के अंत में

चार्ट V.19 : एसटीसीबी के लाभ

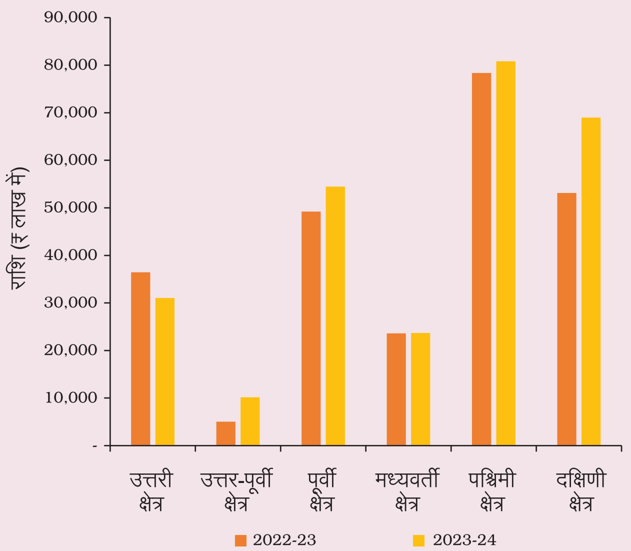

स्रोत : नाबार्ड।

[11] अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में एसटीसीबी ने क्रमशः छठे और चौथे वर्ष घाटे की सूचना दी, और मार्च 2024 के अंत में इन दो एसटीसीबी का संचयी नुकसान ₹35 करोड़ के करीब था।

6.7 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 4.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि गिरावट अधिक थी, मजबूत ऋण वृद्धि के कारण जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई। संदिग्ध श्रेणी के तहत एनपीए लगातार छह वर्षों तक बढ़ने के बाद कम हो गया। एनपीए के लिए अधिक प्रावधान किए गए और इसलिए निवल एनपीए अनुपात में भी सुधार के कारण प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में वृद्धि हुई (सारणी V.16)।

V.40 वर्ष 2023-24 के दौरान, एसटीसीबी के 70 प्रतिशत के जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई, जिसमें अधिक प्रभाव पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र का रहा। पूर्वी क्षेत्र में जीएनपीए अनुपात में मामूली वृद्धि के अलावा जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.3)।

पूंजी पर्याप्तता

V.41 मार्च 2024 के अंत में एसटीसीबी के समेकित सीआरएआर में गिरावट आई, क्योंकि पूंजीगत निधियों में वृद्धि जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि से कम रही (चार्ट V.20)। दो एसटीसीबी का सीआरएआर 9 फीसदी की विनियामकीय न्यूनतम आवश्यकता से कम था।

सारणी V.16: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2023	2024 पी	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	14,296	14,537	-0.3	1.7
i. उप-मानक	4,609 (32.2)	4,974 (34.2)	-14.4	7.9
ii. संदिग्ध	8,292 (58)	8,237 (56.7)	10.0	-0.7
iii. हानि	1,395 (9.8)	1,326 (9.1)	-0.7	-4.9
बी. सकल एनपीए अनुपात (%)	**5.4**	**4.9**	-	-
सी. निवल एनपीएअनुपात (%)	**2.1**	**2.0**	-	-
डी. प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	**67.2**	**68.5**	-	-
ई. मांग और वसूली अनुपात (%)	**91.7**	**92.4**	-	-

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल एनपीए (प्रतिशत में) में शेयर हैं।
2. पी : अनंतिम।
3. मांग और वसूली अनुपात में 2022-23 और 2023-24 के लिए क्रमशः जून 2022 और 2023 के अंत में वसूल किए गए बकाया एनपीए के हिस्से को शामिल किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट V.20: राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता

(मार्च के अंत में)

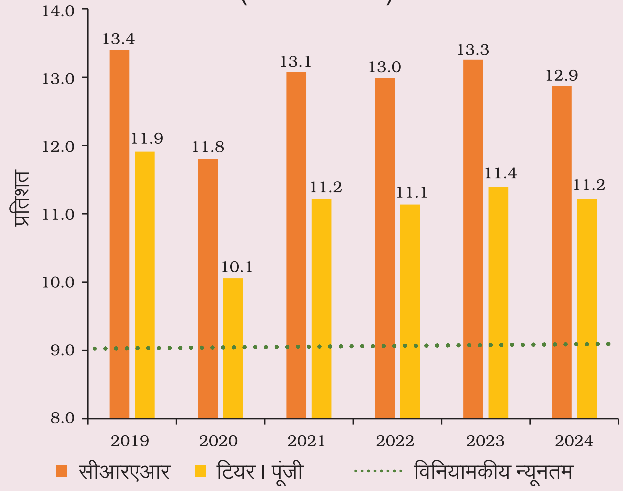

टिप्पणि: केरल के 14 डीसीसीबी में से 13 (मलप्पुरम डीसीसीबी को छोड़कर) 2019-20 के दौरान केरल एसटीसीबी के साथ समामेलित हो गए।

स्रोत : नाबार्ड।

4.1.2. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

V.42 डीसीसीबी सार्वजनिक जमा, एसटीसीबी से उधार और नाबार्ड से पुनर्वित्त के माध्यम से निधियाँ जुटाते हैं। अपने व्यापक शाखा नेटवर्क के कारण, उनके पास सीएएसए जमा तक बेहतर पहुंच है, जो मार्च 2024 के अंत में उनकी कुल जमा राशि का 41.7 प्रतिशत था (एसटीसीबी के लिए 18.6 प्रतिशत की तुलना में)। कुल अग्रिमों का 75 प्रतिशत से अधिक और डीसीसीबी के 96 प्रतिशत कृषि अग्रिम पीएसी/समितियों के लिए है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.43 डीसीसीबी की जमा वृद्धि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10.0 प्रतिशत हो गई, जो एसटीसीबी (6.0 प्रतिशत) से अधिक है। अग्रिमों में उच्च वृद्धि के कारण डीसीसीबी का सी-डी अनुपात मार्च 2023 के अंत में 85.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 86.7 प्रतिशत हो गया (सारणी V.18)।

लाभप्रदता

V.44 डीसीसीबी के एनआईआई में वृद्धि वर्ष 2022-23 के दौरान 14.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 के दौरान 5.4 प्रतिशत हो गई, क्योंकि ब्याज व्यय ब्याज आय की तुलना में

सारणी V.17: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2023	2024पी	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	26,486 (3.8)	28,661 (3.7)	8.2	8.2
2. आरक्षित निधि	28,729 (4.1)	31,701 (4.1)	8.5	10.3
3. जमाराशियां	4,33,358 (62.1)	4,76,610 (62.3)	5.0	10.0
4. उधार	1,47,207 (21.1)	1,61,728 (21.1)	14.5	9.9
5. अन्य देयताएं	61,524 (8.8)	66,876 (8.7)	7.0	8.7
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	33,767 (4.8)	38,705 (5.1)	5.2	14.6
2. निवेश	2,47,942 (35.6)	2,65,692 (34.7)	5.1	7.2
3. ऋण और अग्रिम	3,70,851 (53.2)	4,13,161 (54)	10.2	11.4
4. संचित हानि	8,357 (1.2)	9,405 (1.2)	7.8	12.5
5. अन्य आस्तियां	36,388 (5.2)	38,615 (5)	-2.3	6.1
कुल देयताएं/आस्तियां	**6,97,304 (100.00)**	**7,65,577 (100.00)**	**7.4**	**9.8**

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. पी : अनंतिम

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2022-23	2023-24पी	घट-बढ़ प्रतिशत	
			2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. आय (i +ii)	**46,309 (100.00)**	**52,408 (100.00)**	**11.1**	**13.2**
i. ब्याज आय	43,967 (94.9)	49,989 (95.4)	10.8	13.7
ii. अन्य आय	2,342 (5.1)	2,420 (4.6)	17.9	3.3
बी. व्यय (i+ii+iii)	**44,428 (100.00)**	**50,515 (100.00)**	**10.2**	**13.7**
i. व्यय किए हुए ब्याज	27,600 (62.1)	32,731 (64.8)	8.6	18.6
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	5,639 (12.7)	5,733 (11.3)	15.3	1.7
iii. परिचालन व्यय	11,189 (25.2)	12,051 (23.9)	11.6	7.7
जिसमें से, मजदूरी विधेयक	6,942 (15.6)	7,430 (14.7)	9.7	7.0
सी. लाभ				
i. निवल ब्याज आय	16,367	17,257	14.5	5.4
ii. परिचालन लाभ	6,933	7,107	17.6	2.5
iii. निवल लाभ	1,881	1,894	38.5	0.7

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. पी : अनंतिम

स्रोत: नाबार्ड।

तेजी से बढ़ा (सारणी V.18)। नतीजतन, निवल लाभ वृद्धि पिछले वर्ष के 38.5 प्रतिशत से वर्ष 2023-24 में तेजी से घटकर 0.7 प्रतिशत हो गई, जिसे कम आधार से लाभ हुआ (वर्ष 2021-22 में गिरावट)।

V.45 वर्ष 2023-24 के दौरान, 312 लाभ कमाने वाले डीसीसीबी और 39 घाटे में चलने वाली संस्थाएं थीं। जबकि वर्ष 2023-24 में घाटे में चलने वाले डीसीसीबी की संख्या में गिरावट आई, डीसीसीबी के संचयी हानि में 40.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार का घाटे में रहने वाले डीसीसीबी में 64.1 प्रतिशत हिस्सा है। दूसरी ओर, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों ने डीसीसीबी के कुल लाभ में अधिकतम योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी V.4)।

आस्ति गुणवत्ता

V.46 डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार चौथे वर्ष सुधार हुआ, जिसमें जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के अंत में 12.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 8.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, डीसीसीबी का जीएनपीए अनुपात एसटीसीबी की तुलना में अधिक रहा (चार्ट V.21 और सारणी V.19)। डीसीसीबी वाले 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 15 में जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई। मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों – विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र – में उच्चतम जीएनपीए अनुपात है, और दक्षिणी क्षेत्र में उच्चतम मांग और वसूली अनुपात है (परिशिष्ट सारणी V.4)।

पूंजी पर्याप्तता

V.47 डीसीसीबी का समेकित सीआरएआर और टियर I पूंजी अनुपात मार्च 2024 के अंत में घटकर चार वर्ष के निचले स्तर

चार्ट V.21 : एनपीए अनुपात : एसटीसीबी बनाम डीसीसीबी

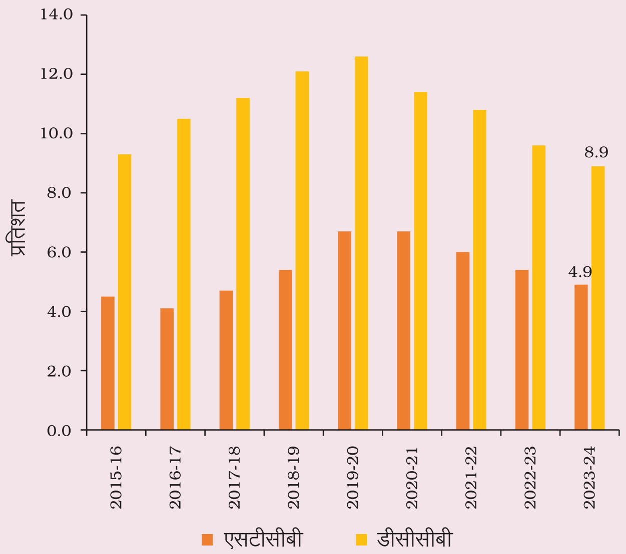

स्रोत : नाबार्ड।

चार्ट V.22: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

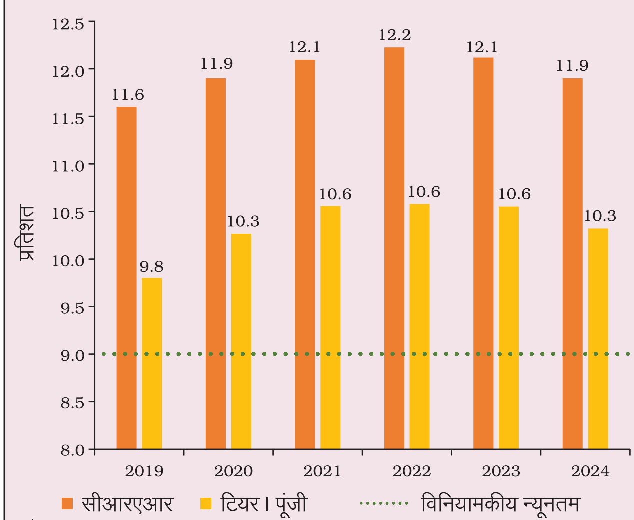

स्रोत : नाबार्ड।

पर आ गया (चार्ट V.22)। हालांकि, 9 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से कम सीआरएआर वाले डीसीसीबी की संख्या मार्च 2023 के अंत में 41 से घटकर मार्च 2024 के अंत में 39 हो गई। 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले 90 प्रतिशत डीसीसीबी छह राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में केंद्रित थे।

सारणी V.19 : ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

	मार्च अंत		t	
	2023	2024पी	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**35,722**	**36,958**	**-1.7**	**3.5**
i) उप-मानक	12,541 (35.1)	13,433 (36.3)	-6.5	7.1
ii) संदिग्ध	20,739 (58.1)	20,912 (56.6)	2.2	0.8
iii) हानि	2,442 (6.8)	2,612 (7.1)	-6.8	7.0
बी. सकल एनपीए अनुपात (%)	**9.6**	**8.9**	-	-
सी. निवल एनपीए अनुपात (%)	**3.9**	**3.4**		
डी. प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	**78.4**	**83.9**		
ई. मांग और वसूली अनुपात (%)	**76.5**	**76.8**	-	-

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल एनपीए (प्रतिशत में) में शेयर हैं।
2. मांग और वसूली अनुपात में 2022-23 और 2023-24 के लिए क्रमशः जून 2022 और 2023 के अंत में वसूल किए गए बकाया एनपीए के हिस्से को शामिल किया गया है।
3. पी : अनंतिम।

स्रोत: नाबार्ड।

4.1.3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

V.48 पीएसीएस सदस्य शेयरधारकों के रूप में व्यक्तियों के साथ ग्रामीण सहकारी समिति शृंखला में सबसे निचले स्तर पर हैं। मार्च 2023 के अंत में, पीएसीएस ने 16.03 करोड़ सदस्यों और 4.9 करोड़ उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किया; जिसमें 45.6 प्रतिशत सदस्य और 57.3 प्रतिशत उधारकर्ता छोटे किसान हैं। उधारकर्ता और सदस्य अनुपात – पीएसीएस की ऋण पैठ को मापने के लिए एक मीट्रिक – मार्च 2022 के अंत में तेजी से घटकर 28.6 प्रतिशत होने के बाद मार्च 2023 के अंत में बढ़कर 30.7 प्रतिशत हो गया। अनुपात में सुधार सदस्यों की संख्या में कमी और उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि दोनों को दर्शाता है (परिशिष्ट सारणी V.5)। पीएसीएस के 80 प्रतिशत से अधिक ऋण अल्प अवधि के थे और कृषि के लिए दिए गए थे। पीएसीएस की कुल संख्या में 29.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पश्चिमी क्षेत्र का इस क्षेत्र में दबदबा है। हालांकि, दक्षिणी क्षेत्र के जमा और ऋण और अग्रिम क्रमशः 79.0 प्रतिशत और 46.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ हावी थे।

V.49 नाबार्ड 5 वर्षों की अवधि में देश भर में लगभग 67,930 कार्यात्मक पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है ताकि उन्हें डिजिटल रूप से सभी ऋण और गैर-ऋण परिचालनों के रिकॉर्ड का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके। योजना का कुल बजट ₹2,516 करोड़ भारत सरकार, राज्य सरकारों और नाबार्ड के बीच साझा किया जाता है। इस परियोजना में साइबर सुरक्षा के साथ क्लाउड-आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर का विकास, राष्ट्रीय स्तर के डेटा रिपोजिटरी (एनएलडीआर) को बनाना और अपलोड करना, प्रशिक्षण और अन्य सहायता सेवाएं शामिल हैं। यह पहल डीसीसीबी और एसटीसीबी के कोर बैंकिंग समाधानों के साथ पीएसीएस के निर्बाध एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा।

V.50 वर्ष 2022-23 में पीएसीएस की आस्ति गुणवत्ता और मांग और वसूली अनुपात में काफी सुधार हुआ; तथापि, उच्च जीएनपीए अनुपात चिंता का कारण बना हुआ है (सारणी V.12)। उच्च उधार और कुल रिज़र्व में वृद्धि के कारण वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसीएस के कुल संसाधनों में वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष पर, अल्पकालिक ऋणों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि के कारण बकाया ऋणों और अग्रिमों में तेजी से विस्तार हुआ (परिशिष्ट सारणी V.6)।

V.51 वर्ष 2022-23 में, पीएसीएस की कुल संख्या का 44.7 प्रतिशत लाभ कमाने वाला था, जिसका समेकित लाभ 18.3 प्रतिशत बढ़कर 2,142 करोड़ रुपये हो गया। घाटे में चल रहे पीएसीएस का समेकित घाटा 4.3 प्रतिशत घटकर ₹3,585 करोड़ हो गया और पूरे क्षेत्र ने वर्ष 2022-23 में ₹1,443 करोड़ की हानि दर्ज की। क्षेत्रीय स्तर पर, केवल पश्चिमी क्षेत्र ने निवल लाभ दर्ज किया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र ने सबसे अधिक हानि दर्ज की (परिशिष्ट सारणी V.7)।

4.2. दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.52 दीर्घकालिक आरसीसी की स्थापना कृषि विकास के लिए दीर्घावधिक वित्त प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी और इसमें राज्य स्तर पर एससीएआरडीबी और जिला/तालुका स्तर पर पीसीएआरडीबी शामिल थे। वर्तमान में, वे पांच राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) में एकात्मक संरचना में काम करते हैं, जहां एससीएआरडीबी राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से परिचालन करते हैं और ग्राहक बैंक की प्रत्यक्ष सदस्यता के आधार पर बैंक से जुड़े होते हैं। छह राज्यों, अर्थात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में एक संघीय संरचना है, अर्थात, एससीएआरडीबी जिला/तालुका स्तर पर संचालित सभी संबद्ध पीसीएआरडीबी की एक शीर्ष इकाई के रूप में काम करते हैं, जो बदले में, सदस्यों को नामांकित करते हैं और उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। दो राज्यों (हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में एक मिश्रित संरचना है जहां एससीएआरडीबी पीसीएआरडीबी के साथ-साथ अपनी शाखाओं के माध्यम से भी काम करते हैं।

V.53 मार्च 2023 के अंत में, 1.08 करोड़ सदस्यों की कुल सदस्यता के साथ 13 एससीएआरडीबी और 608 पीसीएआरडीबी थे, जिनमें से 36 प्रतिशत उधार लेने वाले सदस्य थे। एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी का व्यवसाय मॉडल उधार पर निर्भर करता है, जहां एससीएआरडीबी मुख्य रूप से नाबार्ड से उधार लेते हैं, जबकि पीसीएआरडीबी एससीएआरडीबी से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं (चार्ट V.23ए)। एससीएआरडीबी के पास कम संचित हानि और कुल आस्तियों में ऋण और अग्रिम का उच्च हिस्सा है (चार्ट V.23बी)।

V.54 जनवरी 2024 में, सहकारिता मंत्रालय ने 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में दीर्घकालिक आरसीसी की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य आरसीसी के कार्यकरण में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर के साथ कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराना है।

चार्ट V.23: दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों की देयताएं और आस्तियां: एक तुलना
(मार्च 2023 के अंत में)

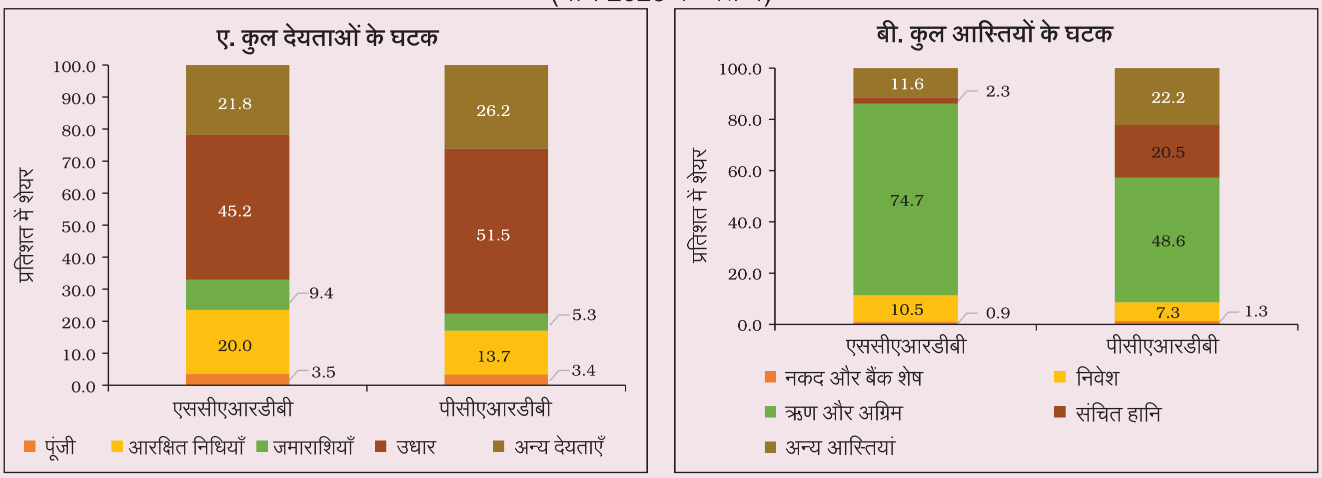

स्रोत : नाबार्ड।

4.2.1. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

V.55 मार्च 2023 के अंत में, एससीएआरडीबी 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालन कर रहे थे, जिसकी 46.7 प्रतिशत शाखाएँ उत्तर प्रदेश में थीं। उधार एससीएआरडीबी की कुल देयताओं का 45.2 प्रतिशत था; इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक उधार नाबार्ड से था, क्योंकि उनका जमा आधार सीमित था। दो वर्षों के विस्तार के बाद, ऋण और अग्रिमों में गिरावट के कारण वर्ष 2022-23 में एससीएआरडीबी के समेकित तुलन-पत्र में कमी आई। देयताओं के पक्ष में, जमा वृद्धि में मंदी के साथ-साथ एससीएआरडीबी के उधार में कमी आई (परिशिष्ट सारणी V.8)।

V.56 अपने तुलन-पत्र में कमी के बावजूद, वर्ष 2022-23 में एससीएआरडीबी के एनआईआई में 25.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि ब्याज आय ब्याज व्यय से अधिक विस्तारित हुई। एनआईआई के साथ-साथ गैर-ब्याज आय में वृद्धि ने हालांकि कम आधार पर निवल लाभ में तेज वृद्धि में योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी V.9)।

V.57 वर्ष 2023-24 में जीएनपीए अनुपात में वृद्धि हुई, और वसूली अनुपात में भी सुधार हुआ (परिशिष्ट सारणी V.10)। दक्षिणी क्षेत्र में सबसे कम जीएनपीए अनुपात और उच्चतम वसूली अनुपात था (परिशिष्ट सारणी V.11)।

4.2.2. प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

V.58 मार्च 2023 के अंत में, 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 608 पीसीएआरडीबी थे। वर्ष के दौरान आस्ति पक्ष पर ऋणों और अग्रिमों में कमी और देयताओं के पक्ष पर उधार में कमी के कारण पीसीएआरडीबी के समेकित तुलन पत्र में कमी देखी गई (परिशिष्ट सारणी V.12)।

V.59 वर्ष 2022-23 के दौरान, पीसीएआरडीबी की आय में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उनके व्यय में कमी आई, जिससे निवल लाभ हुआ। आय में वृद्धि ब्याज और गैर-ब्याज आय दोनों के द्वारा थी, जबकि परिचालन व्यय, विशेष रूप से मजदूरी बिल में गिरावट के कारण कुल व्यय में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.13)। पीसीएआरडीबी वाले आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से पांच ने समेकित निवल हानि दर्ज की।

V.60 अवमानक और संदिग्ध श्रेणियों में कमी के कारण वर्ष 2022-23 के दौरान पीसीएआरडीबी के जीएनपीए अनुपात में मामूली गिरावट आई। हालांकि, जीएनपीए अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक बना रहा, क्योंकि हानि श्रेणी के ऋणों में और विस्तार हुआ (परिशिष्ट सारणी V.14)। अन्य क्षेत्रों में प्रवृत्ति के विपरीत, उत्तरी क्षेत्र के जीएनपीए अनुपात में वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के दौरान उच्चतम जीएनपीए अनुपात और सबसे कम मांग और वसूली अनुपात बना रहा। दूसरी ओर, दक्षिणी क्षेत्र

में सबसे कम जीएनपीए अनुपात और उच्चतम मांग और वसूली अनुपात था (परिशिष्ट सारणी V.15)।

5. समग्र मूल्यांकन

V.61 वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी ने पूंजी बफर, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में सुधार प्रदर्शित किया। हालांकि, वाणिज्यिक बैंकों के सापेक्ष उनकी ऋण और जमा वृद्धि धीमी रही। जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्य जैसे आश्वासन कार्य कुशल जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी द्वारपाल हैं। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी में सुदृढ़ अभिशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें चार-स्तरीय विनियामक ढांचे की शुरूआत, पर्यवेक्षी अपेक्षाओं को बताने के लिए सम्मेलनों के माध्यम से यूसीबी के बोर्ड के निदेशकों और यूसीबी के बीमा कार्यों के प्रमुखों के साथ सीधे जुड़ना। यूसीबी में आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिम को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं।

V.62 ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों में, एसटीसीबी ने लगातार दूसरों से बेहतर प्रदर्शन किया है और वर्ष 2023-24 में उच्च लाभ के साथ-साथ अपनी आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार किया है। आगे देखें तो, सहकारी क्षेत्र को साइबर खतरों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए और तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए तकनीकी प्रगति के अनुसार होना चाहिए।